भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 914
जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
15 माघ, 1947 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

914.श्रीमती लवली आनंदः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री आलोक शर्माः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री नलिन सोरेनः
श्री जुगल किशोरः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने में राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर से दुमका (झारखंड), जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों का ग्रामीण आबादी, महिलाओं और वंचित वर्गों तक सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने में विशेषकर राजस्थान सहित राज्य और जिला-वार क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) दुमका (झारखंड), जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया प्लेटफार्मों की अंतर-संचालनीयता, मापनीयता और बहुभाषी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों में इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) जीआई क्लाउड (मेघराज) पहल के अंतर्गत क्लाउड के माध्यम से उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आईसीटी सेवाएं प्रदान की गई हैं?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित पूरे भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को बढ़ावा दिया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने खुले, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल प्लेटफार्मों के माध्यम से जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) दृष्टिकोण अपनाया है।

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान के लिए (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को सफलतापूर्वक लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रहा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, शासन और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।

डिजिटल सेवाओं में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) - भाषिणी** शुरू किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल मंच के रूप में की गई है। भाषिणी मंच भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है।

इंडिया स्टैक लोकल पोर्टल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई सफल डिजिटल परिवर्तन पहलों को प्रदर्शित करता है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सीखने और दोहराने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है, जो न्यायसंगत, लागत प्रभावी और सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। **794 डिजिटल समाधानों** का राज्य-वार विवरण https://indiastacklocal.in/ पर इंडिया स्टैक लोकल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वैश्विक समुदाय के साथ भारत के डीपीआई की सफलता को साझा करने के लिए कई उपाय किए हैं:

(i) **इंडिया स्टैक ग्लोबल** (https://www.indiastack.global/) को भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और डिजिटल समाधानों की सफलता को प्रदर्शित करने और मित्र देशों द्वारा उन्हें अपनाने और प्रतिकृति की सुविधा के लिए विकसित और लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल आधार, यूपीआई, कोविन, एपीआई सेतु, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), उमंग, दीक्षा, ई-संजीवनी, ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस, ई-कोर्ट, पोषण ट्रैकर, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और पीएम गतिशक्ति सहित 18 प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करता है।

(ii) **ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी** – 2023 में जी20 की भारतीय अध्यक्षता के अंतर्गत, ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी (जीडीपीआईआर) पोर्टल (https://www.dpi.global/) को भारत द्वारा डिजाइन, विकसित और रोल आउट किया गया था। भारत ने जीडीपीआईआर में सबसे अधिक डीपीआई का योगदान दिया।

कुछ प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और डिजिटल प्लेटफार्मों की स्थिति, जो विशेष रूप से ग्रामीण आबादी, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं, इस प्रकार है:

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अब तक **143+ करोड़ आधार आईडी** तैयार की जा चुकी हैं। नामांकन का राज्यवार ब्यौरा https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/ पर उपलब्ध है ।
- **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई):**
  - यूपीआई 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है, और 685 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।
  - भारत में होने वाले 81% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर होने वाले लगभग 49% रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई द्वारा संचालित होते हैं।

- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर ने आम नागरिक को मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक कभी भी पहुंच प्रदान की है। डिजिलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **65.01 करोड़ से** अधिक उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2412 जारीकर्ताओं से 950+ करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार डिजिलॉकर उपयोगकर्ता (आधार सक्षम पंजीकरण) **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग),** सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, ऑपरेशनल है और व्यक्तियों के लिए **2390+ सेवाएं** प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं और डिजिटल सेवाओं का राज्यवार विवरण https://web.umang.gov.in/landing/services पर उपलब्ध है ।

वर्तमान में, 32,205 वर्चुअल मशीनें जीआई क्लाउड (मेघराज) पर चल रही हैं और 2,188 से अधिक सरकारी विभाग अपने अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए जीआई क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं।

*****

अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार डिजिलॉकर उपयोगकर्ता (आधार सक्षम पंजीकरण):

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.21
2	आंध्र प्रदेश	179.23
3	अरुणाचल प्रदेश	3.41
4	असम	94.04
5	बिहार	248.95
6	चंडीगढ़	5.32
7	छत्तीसगढ़	61.16
8	दादरा और नगर हवेली	1.23
9	दमन और दीव	0.62
10	दिल्ली	95.43
11	गोवा	5.26
12	गुजरात	184.14
13	हरियाणा	100.84
14	हिमाचल प्रदेश	25.85
15	जम्मू और कश्मीर	34.15
16	झारखंड	81.99
17	कर्नाटक	265.35
18	केरल	104.02
19	लद्दाख	0.28
20	लक्षद्वीप	0.18
21	मध्य प्रदेश	206.46
22	महाराष्ट्र	406.19
23	मणिपुर	7.26
24	मेघालय	6.05
25	मिजोरम	2.45
26	नागालैंड	3.53
27	ओडिशा	103.39
28	पुडुचेरी	3.85
29	पंजाब	91.45
30	राजस्थान	211.36
31	सिक्किम	1.67
32	तमिलनाडु	194.74
33	तेलंगाना	81.07
34	त्रिपुरा	9.09
35	उत्तर प्रदेश	589.44
36	उत्तराखंड	38.35
37	पश्चिम बंगाल	214.11

*****